**35.8** डिग्री सेल्सियस रहा रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान। यह सामान्य से एक डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बादल छाए रहेंगे।

## न्यूज गैलरी

### सीटेट में 14 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) रविवार को देशभर के 104 शहरों में संपन्न हुई। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा एक से पांच तक और छह से आठवीं तक के स्कूलों में शिक्षक के तौर पर तैनाती मिलेगी। सीटेट के 12वें संस्करण में दो पाली में परीक्षा हुई, इसमें देशभर से 14 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। सीबीएसई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीटेट के लिए 20 लाख 84 हजार 174 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 14 लाख 14 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें कक्षा एक से पांचवीं तक के शिक्षक पद के लिए 8 लाख 17 हजार 894 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इनकी परीक्षा प्रथम पाली में हुई। इन्हें प्रश्न पत्र एक दिया गया था। कक्षा छठी से आठवीं तक के शिक्षक पद के लिए 4 लाख 27 हजार 897 अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली में परीक्षा दी। इन्हें प्रश्नपत्र दो दिया गया था। 8 लाख 38 हजार 383 अभ्यर्थियों ने दोनों पेपरों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रश्नपत्र एक के लिए ऐसे 5 लाख 40 हजार 649 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि प्रश्नपत्र दो के लिए 2 लाख 74 हजार 438 शामिल हुए। दोनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 5, 84 927 है। परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने बोर्ड की अध्यक्ष अनीता करवल एवं सचिव अनुराग त्रिपाठी को बधाई दी। डॉ. निशंक ने बोर्ड के प्रौद्योगिकी विकास, डिजिटल दस्तावेजों की उपलब्धता एवं कार्बन उत्सर्जन की कमी में बोर्ड की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। (जासं)

### विस अध्यक्ष के खिलाफ हाई कोर्ट गए विधायक

**नई दिल्ली** : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के दो बागी विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बागी विधायक देवेंद्र सहरावत एवं अनिल वाजपेयी ने उन पर निष्पक्ष सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। दोनों विधायकों की सदस्यता रद करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई कर रहे हैं। विधायक अनिल वाजपेयी ने याचिका में कहा कि विस अध्यक्ष को किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दोनों विधायकों ने कहा कि उन्होंने न तो आम आदमी पार्टी छोड़ी है और न ही भाजपा में शामिल हुए हैं। बावजूद इसके विस अध्यक्ष ने एक अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। (जासं)

**योजना** ▶ सीएम ने नई दिल्ली विस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ

# दिल्ली में बढ़ते अपराध को रोकने में मदद करेंगे सीसीटीवी कैमरे : केजरीवाल

### कहा, लगाए जा रहे हैं तीन लाख सीसीटीवी कैमरे, विश्वास का वातावरण बनेगा

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। दिल्लीवासियों में सुरक्षा को लेकर भय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगने से उनमें विश्वास का वातावरण बनेगा। वह नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट के शुभारंभ अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।

केजरीवाल ने रविवार को पंडारा रोड और लक्ष्मीबाई नगर के रिहायशी इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने उन परिवारों को धन्यवाद भी दिया जिन्होंने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। इसलिए पूरी दिल्ली में तीन लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि कोई गलत काम करेगा तो उसकी फोटो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगी। इससे गलत कामों में कमी आएगी। अपराधों में कमी आएगी। यदि अपराध हो भी जाएगा तो पुलिस को अपराधी को पकड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सीसीटीवी कैमरे बहुत हाई क्वालिटी के हैं और रात में भी काम करते हैं।

पंडारा रोड स्थित सरकारी आवासीय कॉलोनी में रविवार को सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट के शुभारंभ अवसर पर कैमरे के बारे में लोगों से बात करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने महिलाओं सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। पारस कुमार

पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में मैं द्वारका में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची से मिला था। आरोपित कुछ ही घंटे में पकड़ा गया क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। चैन स्नैचिंग की बढ़ते मामलों पर केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड होने के बाद जवाबदेही तय होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले तीन वर्षों में विपक्ष ने पूरी कोशिश कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे न लगने पाए। हमने उपराज्यपाल के यहां धरना देकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की फाइल पास करवाई। मालूम हो कि केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 180 से ज्यादा बैठकें की हैं। इन बैठकों में उन्होंने ये भी फीडबैक लिया कि किन-किन जगहों पर सीसीटीवी की जरूरत है। ये पूरा प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों की फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। सरकार अब जल्द ही कैमरे लगाने जा रही है।

# आकाश से होगी डीडीए की जमीन की निगरानी

**संजीव गुप्ता, नई दिल्ली**

अपनी जमीन को अवैध कब्जों एवं अतिक्रमण से बचाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब सेटेलाइट की मदद लेगा। सेटेलाइट के जरिये न सिर्फ जमीन की निगरानी की जाएगी, बल्कि कहीं कोई गड़बड़ी मिलने पर अविलंब कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके लिए डीडीए ने दिल्ली में अपनी जमीन को चिह्नित कर लिया है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर इसकी सेटेलाइट से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। यह निगरानी अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है।

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में डीडीए के स्वामित्व वाली करीब पांच हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी है। यह जमीन छोटे-बड़े करीब ढाई हजार प्लाटों के रूप में है। इस जमीन को अवैध कब्जे और अतिक्रमण से बचाने के लिए डीडीए न सिर्फ गंभीर है, बल्कि पुख्ता योजना भी तैयार की है। इसके लिए पुराना रिकॉर्ड और नक्शे निकालकर डीडीए ने अपनी पूरी जमीन चिह्नित कर ली है। इसकी डिजिटल मैपिंग भी तैयार की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक इस कार्य के लिए डीडीए ने इसरो के साथ अनुबंध किया है। इसके लिए इसरो को भुगतान भी किया जा रहा है। जमीन की डिजिटल मैपिंग के बाद दिल्ली की सभी कॉलोनियों और संपत्तियों की ज्योग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम (जीआइएस) से भी मैपिंग की जाएगी ताकि डीडीए के पास दिल्ली का पूरा डिजिटल मैप मौजूद रहे। मतलब, डीडीए जब चाहे, महज एक क्लिक पर कंप्यूटर पर कहीं का भी जायजा ले सके। इससे न केवल डीडीए की जमीन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि मास्टर प्लान और जोनल प्लान से इतर कहीं उस जमीन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है।

> डीडीए की खाली जमीन की सेटेलाइट निगरानी के लिए व्यवस्था करीब-करीब पूरी हो गई है। इसरो इसी माह के अंत तक हमें पूरा नेटवर्क तैयार करके दे देगा। संभावना है कि अगले महीने से सेटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए। इस व्यवस्था के जरिये खाली जमीन के साथ-साथ डीडीए की प्लानिंग पर क्रियान्वयन को लेकर लगातार निगाह रखी जाएगी। समय-समय पर उपराज्यपाल जो कि डीडीए के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी इसकी रिपोर्ट जाएगी। उल्लंघन पर यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
>
> -तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

# गृह मंत्रालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षक की घर में चाकू से गोद कर हत्या

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

- आनंद सिंह के सिर पर पीछे से भारी चीज से भी किए गए वार
- रहस्यमय हालात में हुई हत्या के मामले में परिजन भी शक के घेरे में

गृह मंत्रालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित मीठापुर की है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रहस्यमय हालात में हुई हत्या के मामले में परिजन भी शक के घेरे में हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

डीसीपी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि मूलरूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले स्थित बनिहार गढ़ गांव के रहने वाले 43 वर्षीय आनंद सिंह दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम नगर, मीठापुर में रहते थे। वह गृह मंत्रालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक थे और आइटीओ स्थित कार्यालय में बैठते थे। शुक्रवार रात करीब 11 बजे वह घर लौटे और कमरे में सोने चले गए। उस वक्त घर में उनकी पत्नी, दो बेटे, एक बेटी व भाई मुकेश थे। आनंद सिंह देर रात अलग कमरे में सो रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कमरों में। रात करीब सवा तीन बजे पत्नी जागी तो कमरे से खून निकलता देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने देवर मुकेश, दोनों बेटों व बेटी को जानकारी दी। परिजनों के मुताबिक उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो आनंद जमीन पर पड़े थे। उनके ऊपर कूलर गिरा था। भाई मुकेश व बड़े बेटे प्रदीप ने कूलर उठाया तो पता चला कि उनकी पीठ पर चाकू से वार किए गए थे। चाकू से गोदकर व सिर पर पीछे से भारी चीज से वारकर उनकी हत्या की गई थी। सूचना पर शनिवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम को भेजा।

डीसीपी का कहना है कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घर से कोई सामान गायब नहीं है। परिवार के इतने सदस्यों के घर में होने के बावजूद हमलावर चाकू से वारकर हत्या को अंजाम देता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। रहस्यमय हत्या का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। मृतक के परिजनों व अन्य परिचितों से पूछताछ की जा रही है।

### जानकार का हाथ होने का अंदेशा

आनंद सिंह की हत्या में उनके किसी जानकार का हाथ होने का अंदेशा है। परिजनों के मुताबिक वह शुक्रवार रात करीब 11 बजे आते ही कमरे में सोने चले गए, लेकिन गर्मी के चलते उन्होंने गेट बंद नहीं किया। मेन गेट भी खुला हुआ था। ऐसे में एक आशंका यह भी है कि देर रात कोई ऐसा शख्स घर में आया, जिसे आनंद जानते थे, इसीलिए वह आसानी से दाखिल हुआ और हत्या कर फरार हो गया।

### देरी से सूचना देना संदेह के घेरे में

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आनंद सिंह की हत्या की जानकारी परिजनों को करीब सवा तीन बजे लगी। इसके बाद उन्होंने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को फोन कर बुला लिया, लेकिन पुलिस को जानकारी करीब पौने दो घंटे बाद सुबह पांच बजे दी। पुलिस को देरी से सूचना देना भी परिजनों की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

# डीयू की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान केंद्र में लगी आग, हड़कंप

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

- तीन सौ छात्राएं आई थीं परीक्षा देने आधे घंटे तक रही अफरातफरी
- 45 मिनट विलंब से शुरू हुई बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजूकेशन की परीक्षा

दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएलएड (बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजूकेशन) कोर्स में दाखिले के लिए ओल्ड पालम रोड स्थित परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन टेस्ट के दौरान आग लग गई। इससे परीक्षा देने आईं करीब तीन सौ छात्राएं और अभिभावकों में अफरातफरी फैल गई। इस कारण करीब 45 मिनट विलंब से परीक्षा शुरू हो सकी। प्रथमदृष्टया आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

रविवार दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने वाली थी। केंद्र के तीनों फ्लोर पर 11 बजे सभी छात्राएं अपने-अपने स्थान पर बैठ गई थीं। 11.29 बजे ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई और इसके साथ ऊपरी मंजिल पर भी धुआं फैल गया। सभी छात्राएं इधर-उधर भागने लगीं।

इसी दौरान प्रथम तल पर किसी ने प्रवेश द्वार बंद कर दिया, जिससे छात्राएं बाहर नहीं निकल पा रही थीं। इस पर अभिभावक ऊपर पहुंचे और प्रवेश द्वार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। किसी तरह दरवाजा खोला गया और छात्राओं को बाहर निकाला गया। केंद्र के कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से इलेक्ट्रिक पैनल में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। अग्निशमन विभाग व आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची और छात्राओं को नीचे उतारा गया। छात्राओं ने बताया कि धुआं भरने से सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। कुछ छात्राएं तो इतनी डरी हुई थीं कि वे सीढ़ी से नीचे भी नहीं आ रही थीं। अग्निशमन विभाग ने छह फायर टेंडर भेजे थे। सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

द्वारका स्थित पुराना पालम रोड पर परीक्षा सेंटर में आग लगने के बाद जमा अभिभावकों की भीड़। शार्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। हरि प्रकाश

**घटना के बाद कई छात्राएं चली गईं घर** : घटना के बाद छात्राएं बहुत डरी हुई थीं। आधे घंटे बाद अधिकारियों ने फिर से परीक्षा की अनुमति दी, तब भी छात्राएं ऊपर जाने से घबरा रही थीं। अभिभावकों ने बताया कि घटना से करीब दस छात्राएं इतना डर गई थीं कि वे बिना परीक्षा दिए ही घर चली गईं।

### नहीं मिली थी फायर से एनओसी जिला प्रशासन भेजेगा नोटिस

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे दक्षिणी पश्चिमी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने इमारत में कई खामियां पाईं। किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी जरूरी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया।

डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अफसर विनोद भारद्वाज ने बताया कि यहां जबरदस्त लापरवाही नजर आई है। इमारत में कोई आपातकालीन द्वार नहीं है। साथ ही घटना के बाद मुख्य निकास द्वार को भी नहीं खोला गया। इससे छात्राओं व अभिभावकों को काफी परेशानी हुई। साथ ही इमारत की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल पर आग से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। ऐसे में आग अगर ऊपरी तल पर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बिल्डिंग में पानी के टैंक भी नहीं नजर आए।

#### करीब दो घंटे तक की जांच

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बचाव कार्य के बाद करीब दो घंटे तक बिल्डिंग का निरीक्षण किया और इसमें मिली खामियों को नोट किया। इस घटना से पहले जनकपुरी इलाके में भी एक घटना हुई थी, जहां एक हॉस्टल के इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई थी। यह इस इलाके की लगातार दूसरी घटना है।

उन्होंने कहा कि दक्षिणी पश्चिमी जिला उपायुक्त राहुल सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और हमें रिपोर्ट बनाने को कहा है। इसके आधार पर नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां पर कई ऐसे केंद्र चल रहे हैं, जिनमें अनियमितताएं हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इलाके के ऐसे सेंटरों का निरीक्षण करेगा और जहां-जहां खामी मिलेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

### याद आ गया सूरत हादसा

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : परीक्षा केंद्र पर आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। एक साथ सैकड़ों अभिभावक सेंटर के ऊपरी तल पर जाने लगे। इस दौरान कई लोग गिर भी गए। अभिभावकों ने कहा कि जैसे ही आग लगी, हमारे जेहन में सूरत हादसे की तस्वीर उभरने लगी। हर कोई अपने-अपने बच्चे को देखने के पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल की ओर भागा। बच्चों के चेहरे पर भी दहशत व्याप्त थी।

### एयरलिफ्ट से निकाला बाहर

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस समय आग लगी, उस वक्त सैकड़ों छात्राएं और कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद थे। घटना के बाद अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और करीब दो सौ लोगों को एयरलिफ्ट से नीचे उतारा गया। घटना के बाद पचास से साठ लोग सीढ़ी के सहारे बाहर निकलने में सफल रहे।

# थाने से चलाई गई कैट्स एंबुलेंस

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

अनुबंधित कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कैट्स एंबुलेंस सेवा चरमरा गई है। हालांकि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग हड़ताली कर्मचारियों को बकाया वेतन देने को तैयार हो चुका है। फिर भी कर्मचारी ड्यूटी पर लौटने को तैयार नहीं हैं। वे एक सप्ताह से एंबुलेंस का निजीकरण रद करने की मांग पर अड़े हैं। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने भी एंबुलेंस सेवा को पटरी पर लाने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अस्पतालों से मेल नर्स और चालक एंबुलेंस पर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही आठ जिलों के 67 थानों से एंबुलेंस का परिचालन शुरू किया गया है।

लोगों को कम समय में एंबुलेंस उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली भर में करीब 200 प्वाइंट बने हैं। कई अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में भी कैट्स एंबुलेंस तैनात रहती हैं। इन दिनों वहां से एंबुलेंस हटा ली गई हैं। कैट्स एंबुलेंस सेवा के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों ने 80 फीसद एंबुलेंस के टायर पंचर कर दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक-एक टायर में 10-12 पंचर हैं। इससे रविवार को कर्मचारियों की व्यवस्था होने के बावजूद सिर्फ 60 एंबुलेंस सड़क पर उतर पाईं। कैट्स एंबुलेंस सेवा ने थानों में खड़ी करने का प्वाइंट बनाया है। कंट्रोल रूम से कॉल मिलने पर ये एंबुलेंस थाने से मरीज को लेने रवाना हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी के दौरान एंबुलेंस में एक पुलिसकर्मी के मौजूद रहने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अस्पतालों से 100 मेल नर्स व 12 चालक कुछ समय के लिए एंबुलेंस पर तैनात किए गए हैं। साथ ही कैट्स एंबुलेंस सेवा के 135 स्थायी कर्मचारी भी एंबुलेंस के परिचालन में लगाए गए हैं। इसके अलावा संचालक कंपनी जीवीके-ईएमआरआइ ने भी कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

अनुबंधित कर्मचारियों की ओर से एंबुलेंस को जगह-जगह रोकने की शिकायत के बाद हर थाने में एंबुलेंस की सुरक्षा पुलिस कर रही है। जारण

**महज 100 मरीजों की मदद के लिए पहुंची एंबुलेंस** : मौजूदा समय में कैट्स में 263 एंबुलेंस हैं। इसमें 31 एएलएस (एडवांस लाइफ सपोर्ट), 108 बीएलएस (बेसिक लाइफ सपोर्ट) व 124 सामान्य एंबुलेंस हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के बावजूद रविवार को महज 100 मरीजों की मदद के लिए एंबुलेंस पहुंच पाई, जबकि सामान्य तौर पर करीब 1050 मरीजों को कैट्स एंबुलेंस अस्पताल पहुंचाती है। इससे स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था नाकाफी है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हड़ताली कर्मचारियों की नियुक्ति पुरानी संचालक कंपनी ने की थी। उस कंपनी का अनुबंध खत्म होने के बाद कर्मचारियों का अनुबंध भी खत्म हो गया है। फिर भी यह तय किया गया था कि नई संचालक कंपनी जीवीके-ईएमआरआइ पुराने कर्मचारियों को ही रखेगी, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण संचालक कंपनी को नए कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दे दिया गया है। कंपनी नियुक्ति भी शुरू कर चुकी है। ऐसे में यदि हड़ताली कर्मचारी जल्द हड़ताल तोड़कर ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी उन्हें ड्यूटी पर रखने को तैयार है।

### पहली बार पेपरलेस होगी मुख्य न्यायमूर्ति की अदालत

**जासं, नई दिल्ली** : दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति की अदालत पहली बार पेपरलेस होगी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कार्यभार संभालने के बाद यह पहला निर्देश दिया है। ऐसे में अब मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ वाली अदालत में सभी मामलों की सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर होगी। अभी तक कॉमर्शियल कोर्ट और कुछ एकल पीठ को ही आंशिक या फिर पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सका है, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली अदालत में अब तक ऐसा नहीं हो सका था।

मुख्य न्यायमूर्ति की अदालत का पेपरलेस होना बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यहां पर हर तरह के मामले दाखिल होते हैं। इनमें जनहित याचिका के साथ ही संवैधानिक, टैक्स, और कॉमर्शियल मामले भी शामिल हैं। एकल पीठ के लिए पेपरलेस होना आसान है, लेकिन कोर्ट संख्या-एक जहां विभिन्न मामलों से जुड़े शपथ पत्र, स्थिति रिपोर्ट और याचिका दाखिल होती हैं, उसे पेपरलेस करना बड़ी चुनौती होगी। उच्च पीठ के पेपरलेस होने से अन्य एकल पीठ और सहयोगियों को संदेश जाएगा कि वह भी न सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ें, बल्कि प्रतिदिन की सुनवाई भी पेपरलेस करें।

**बदलाव**

डीएमआरसी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद मजेंटा और पिंक लाइन की मेट्रो ट्रेनों से चरणबद्ध तरीके से चालकों को हटाने की तैयारी में है

# अगले साल से चालक के बगैर चलेगी मेट्रो

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

फेज-तीन की पिंक व मजेंटा लाइन पर चालक रहित (स्वचालित) मेट्रो के परिचालन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) तीन महीने के अंदर तकनीकी सलाहकार कंपनी की नियुक्ति करेगा। यह सलाहकार कंपनी पिंक लाइन व मजेंटा लाइन के बुनियादी ढांचे, तकनीक व उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान डीएमआरसी की तैयारियों की पूरी समीक्षा भी होगी। इसके बाद सलाहकार कंपनी डीएमआरसी को रिपोर्ट सौंपेगी। उम्मीद है कि अगले साल से चालक के बगैर पिंक व मजेंटा लाइन पर मेट्रो दौड़ने लगेगी।

मौजूदा समय में इन दोनों लाइनों पर भी ट्रेन ऑपरेटर मेट्रो का परिचालन करते हैं। 38 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम-बोटेनिकल गार्डन) व 58.59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन (शिव विहार-मजलिस पार्क) पर संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इन दोनों कॉरिडोर पर कंट्रोल रूम से तकनीक के सहारे मेट्रो ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। यही वजह है कि इन दोनों कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी ने करीब 80 चालक रहित तकनीक पर आधारित मेट्रो ट्रेनें खरीदी हैं। हालांकि इनमें अभी चालक मौजूद रहते हैं। डीएमआरसी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद इन दोनों लाइनों की मेट्रो ट्रेनों से चरणबद्ध तरीके से चालकों को हटाने की तैयारी में है। यही वजह है कि डीएमआरसी ने फरवरी में सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। सलाहकार कंपनी दोनों मेट्रो लाइन के ट्रैक, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी), ओएचई (ओवर हेड इक्यूपमेंट), सिग्नल सिस्टम, मेट्रो ट्रेन, डिपो की बुनियादी सुविधाओं और रखरखाव का निरीक्षण करेगी। इस दौरान वह यह भी देखेगी कि चालक के बगैर मेट्रो का परिचालन करना कितना सुरक्षित होगा। नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित हैं या नहीं। इसलिए सलाहकार की नियुक्ति के बाद रिपोर्ट तैयार करने में भी कुछ वक्त लगेगा।

तीन महीने के अंदर तकनीकी सलाहकार कंपनी की नियुक्ति कर दी जाएगी। (फाइल)

### चमचमाते हुए नजर आएंगे रेड लाइन के 21 पुराने मेट्रो स्टेशन

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली** : रेड लाइन मेट्रो के सभी 21 पुराने स्टेशन चमचमाते हुए नजर आएंगे। इन्हें 23. 70 करोड़ खर्च कर आकर्षक बनाया जाएगा। डीएमआरसी ने तीन हिस्सों में इन स्टेशनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। उम्मीद है कि 11 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। इससे सभी स्टेशनों का स्वरूप बदल जाएगा और ये नए आकर्षक रूप में दिखने लगेंगे। उल्लेखनीय है कि रेड लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे पुराना कॉरिडोर है। दिसंबर 2002 में सबसे पहले इस कॉरिडोर पर ही तीस हजारी से शाहदरा के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था। मौजूदा समय में इस कॉरिडोर की लंबाई 34.4 किलोमीटर है, जिसमें से 9.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर (दिलशाद गार्डन-बस अड्डा गाजियाबाद) का निर्माण फेज-तीन में हुआ है। इस नए कॉरिडोर पर इस साल मार्च में ही परिचालन शुरू हुआ। रेड लाइन के 24.9 किलोमीटर लंबे पुराने कॉरिडोर पर 21 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों का रंगरोगन फीका पड़ चुका है। स्टेशन के पास बने फुटपाथों की टाइल्स भी जगह-जगह निकली पड़ी हैं। रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर सीढ़ियों के नीचे की दीवार में दरार भी आ गई है।

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो के परिचालन में काफी हद तक ऑटोमैटिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। पुरानी मेट्रो में चालक का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने पर ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और मेट्रो की रफ्तार स्वतः धीमी हो जाती है।

# जबरन सेवानिवृत्त किए जाएंगे भ्रष्ट अधिकारी

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली**

- भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सूचना बनाने के सीएम ने दिए निर्देश

भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें जबरन सेवानिवृत्त करने के उप राज्यपाल के निर्णय पर अब दिल्ली सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्य सचिव विजय कुमार देव के साथ बैठक की है।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सभी सदस्यों को अपने-अपने विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जा सके। यह कार्रवाई सेंट्रल सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स, 1972 के फंडामेंटल रूल 56 (जे) के तहत भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के केंद्र सरकार की पहल के आधार की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर एक माह में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली सरकार शुरू से ही भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरता बरतने की नीति पर काम करती रही है। केजरीवाल जब 2013-14 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसे दौरान 49 दिनों के कार्यकाल में ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया था। वर्तमान कार्यकाल में भी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति पूरी तरह से कठोर रही है। सरकार का ऐसा मानना है कि ऐसे अधिकारी दिल्ली के लोगों के लिए बनाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बर्बाद करते हैं और जनता के हक के पैसों से अपना घर भरते हैं।